



Garvi Gujarat
गारवी गुजरात
लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

किंमत : 00.50 पैसा

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
गरवी गुजरात हिंदी चैनल देखिये

सम्पादकीय

राजनीति में अपराधियों का घालमेल

राजनीति से अपराधियों की सफाई ही लोकतंत्र को बचाने का सबसे बड़ा उपाय है। सवाल है कि क्या हमारे राजनीतिक दल और नेता इस सच्चाई को स्वीकार कर अपनी राजनीति को स्वच्छ बनाने का साहस दिखाएंगे, ऐसा तत्काल तो संभव नहीं दिख रहा है। ऐसे में राजनीति से अपराधीकरण को मुक्त करने की बात सिर्ष छलावा है। लोकतंत्र की शुचिता के लिए बढ़ता खतरा अपराधियों का राजनीतिकरण! एक ताजा रिपोर्ट ने भारतीय राजनीति की हकीकत को बेपर्दा कर दिया है. इस रिपोर्ट में बताया गया कि देश के 643 मंत्रियों में से 302 (47%) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं. इनमें से 174 मंत्री गंभीर अपराधों जैसे हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध में आरोपित हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में राजनीति के अपराधीकरण को रोकने की बात लंबे अरसे से हो रही है। चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट के तमाम प्रयासों के बावजूद देश की राजनीति में अपराधीकरण कम होने के बजाए बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि राजनीति में अपराधी तत्वों की घुसपैठ कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन जिस पैमाने पर यह बढ़ा है, वह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। एसोसिएशन फॉर डेमोकैटिक रिफार्म्स की ताजा रिपोर्ट इस सच्चाई को बयान करती है कि देश के लगभग आधे मंत्री ऐसे हैं, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर मामले भी शामिल हैं। अब सवाल यह आता है कि जब कानून बनाने और उसे लागू कराने वाले ही दागी होंगे तो क्या वे सचमुच न्याय और निष्पक्ष शासन की रक्षा कर पाएंगे ? एडीआर के एक विश्लेषण के अनुसार देश के लगभग 47 प्रतिशत मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है, जिनमें हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। यह रिपोर्ट वेद सरकार द्वारा उन तीन विधेयकों को संसद में पेश किए जाने के कुछ दिन बाद आई है, जिनमें गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी के बाद 30 दिन तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। हाल ही में एडीआर ने 27 राज्य विधानसभाओं, तीन वेंदशासित प्रदेशों और वेंद्रीय मंत्रिपरिषद के 643 मंत्रियों के हलफनामों का अध्ययन किया और पाया कि 302 मंत्रियों, यानी कुल मंत्रियों के 47 प्रतिशत के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन 302 मंत्रियों में से 174 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। विश्लेषण के अनुसार भाजपा के 336 मंत्रियों में से 136 यानी 40 प्रतिशत ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है और 88 यानी 26 प्रतिशत पर गंभीर आरोप हैं। कांग्रेस शासित चार राज्यों में पाटा के 45 मंत्रियों यानी 74 प्रतिशत पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 18 यानी 30 प्रतिशत के खिलाफ गंभीर अपराध दर्ज हैं। द्रमुक के 31 मंत्रियों में से 27 यानी लगभग 87 प्रतिशत पर आपराधिक आरोप हैं, जबकि 14 यानी 45 प्रतिशत पर गंभीर मामले दर्ज हैं। तृणमूल कांग्रेस के भी 40 में से 13 मंत्रियों यानी 33 प्रतिशत पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 8 वानी 20 प्रतिशत पर गंभीर आरोप हैं। तेलुगु देशम पाटा (तेदेपा) का अनुपात सबसे ज्यादा है, जिसके 23 में से 22 मंत्रियों यानी 96 प्रतिशत पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 13 यानी 57 प्रतिशत पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आप के 16 में से 11 यानी 69 प्रतिशत पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि पांच यानी 31 प्रतिशत पर गंभीर मामले दर्ज हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 72 वेंद्रीय मंत्रियों में से 29 यानी 40 प्रतिशत ने अपने हलफनामों में आपराधिक मामले घोषित किए हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु विहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पुदुचेरी में 60 प्रतिशत से ज्यादा मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके विपरीत हरियाणा, जम्मु-कश्मीर, नागालैंड और उत्तराखंड के मंत्रियों ने अपने खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होने की सूचना दी है। देखा जाए तो सभी परटियों में दागी नेता है, जबकि देश के सभी दल अपराध मु्त राजनीति की बात करते हैं।

आंकड़ों को देखने के बाद साफ है कि हिंदुस्तान की सियासत आज जिस रास्ते पर चल रही है वह भ्रष्टाचार और अपराध से लंबालब है। आपको पता है चुनाव में बढ़ता धनबल, बाहुबल और अपराधा करण लोकतंत्र को अंदर ही अंदर खा रहा है। जब कानून के निमातों और रखवाले ही अपराध में सने होंगे तो उनसे वैसे उम्मीदी की जा सकती है कि लोकतंत्र को स्वस्थ रख सवेंगे। पहले तो बिहार और उत्तर प्रदेश को ही आपराधिक राजनीति का गढ़ कहा जाता था, लेकिन पिछले दो-तीन दशकों से सभी राज्यों में ऐसी प्रवृति के नेताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। आज नेताओं का उद्देश्य चुनाव जीतकर देश सेवा करना नहीं, बल्कि सत्ता हासिल कर हुबूहत करना है। कालेजियम व्यवस्था के रहते हमारी न्यायपालिका को भी पूर्ण पवित्र नहीं कहा जा सकता है। राजनीति का अपराधीकरण केवल संसद और विधानसभाओं को ही प्रभावित नहीं करता, वरन समाज और लोकतंत्र की जड़ें खोखली कर देता है। लेकिन चिता की बात यह है कि राजनीतिक परटियों के द्वारा चुनाव जीतने के लिए दागी उम्मीदवारों को टिकट देने में कोई परहेज नहीं किया जाता है। 'हमाम में सभी नंगे हैं' की तर्ज पर सभी राजनीतिक परटियों की गोद में ऐसे अनेक नेताओं की किलकारियां गूंजती हैं, जो अपराध में आवंट डूबे हैं। चुनावों में अपराधीकरण बढ़ने का बड़ा कारण चुनावी व्यवस्था की खामियां हैं। चुनाव लड़ने के लिए अपार धन की जरूरत होती है, और यही धनबल राजनीति में अपराधियों के लिए रास्ता खोल देता है। अपराध से अंजित धन चुनावी मैदान में खर्च होता है और उसके बदले सत्ता का संरक्षण अपराधियों को मिलता है। बाहुबल और धनबल के सहारे चुनाव जीतने वाले जनप्रतिनिधि जनता के प्रति कम और अपने अपराधी गिरोह के प्रति ज्यादा जवाबदेह हो जाते हैं। हालांकि इस दिशा में पिछले कुछ समय में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के तरफ से कई कदम उठाए गए हैं, इनके भी हाथ बंधे हुए हैं। शीर्ष न्यायालय बार-बार कह चुका है। चुका है कि गंभीर आपराधिक मामलों में पंसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दल वोट बैंक की मजबूरी में ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देने से बाज नहीं आते हैं। राजनीति में अपराध को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि वह ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव मैदान से बाहर कर सके। साथ ही चुनावी खर्च की सीमा का कड़ाई से पालन और पारदर्शा पंडिग व्यवस्था की जरूरी है। कानून से ज्यादा जरूरी है राजनीतिक दलों का आत्मसंयम और नैतिकता। यदि दल अपराधियों को टिकट न दें तो यह समस्या स्वतः कम हो जाएगी। लेकिन आज की राजनीति में सत्ता की लालसा इतनी प्रबल है कि दल अपराधियों को भी सिर-आंखों पर बिठाने से हिचकते नहीं। जब तक दल खुद यह संकल्प नहीं लेंगे कि वे स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों को ही आगे बढ़ाएंगे, तब तक लोकतंत्र में शुचिता की उम्मीद करना व्यर्थ है। भारत का लोकतंत्र विश्व के लिए आदर्श माना जाता है, लेकिन यह तभी टिकेगा जब इसकी जड़ें मजबूत हों। अपराधीकरण और भ्रष्टाचार लोकतंत्र की नींव को खोखला कर रहे हैं। यदि आज ठोस कदम नहीं उठाए गए तो कल जनता का भरोसा इस व्यवस्था से पूरी तरह उठ जाएगा। लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है, बल्कि यह जनता के प्रति जवाबदेही, पारदर्शिता और नैतिकता का प्रतीक है। राजनीति से अपराधियों की सफाई ही लोकतंत्र को बचाने का सबसे बड़ा उपाय है। सवाल है कि क्या हमारे राजनीतिक दल और नेता इस सच्चाई को स्वीकार कर अपनी राजनीति को स्वच्छ बनाने का साहस दिखाएंगे, ऐसा तत्काल तो संभव नहीं दिख रहा है। ऐसे में राजनीति से अपराधीकरण को मुक्त करने की बात सिर्ष छलावा है।

रूस पर प्रतिबंध लगाने और चीन पर 50-100% टैरिफ लगाने के लिए ट्रम्प ने चली चाल! नाटो पर अब बनाया दबाव

(जीएनएस)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों से रूसी तेल खरीदना बंद करने का आग्रह किया है। उन्होंने रूस पर मॉस्को की पकड़ तोड़ने के लिए चीन पर 50-100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रस्ताव भी दिया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि इन प्रस्तावों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो अमेरिकी संसाधनों की बबादी होगी।

शनिवार को ट्रंप ने नाटो देशों पर रूस से तेल खरीद बंद करने और उस पर प्रतिबंध लगाने का दबाव डाला। उन्होंने यूक्रेन युद्ध समाप्त होने तक चीन पर 50-100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का सुझाव दिया।

ट्रंप की यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, जिसमें भारतीय तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत शुल्क भी शामिल था,

लेकिन चीन के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

नाटो सदस्यों और "दुनिया" को संबोधित एक पत्र में, ट्रंप ने लिखा, "मैं रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूँ, जब सभी नाटो राष्ट्र लगाने का प्रस्ताव भी दिया। और जब सभी नाटो राष्ट्र रूस से तेल खरीदना बंद कर दें। जैसा कि आप जानते हैं, जीतने के लिए नाटो की प्रतिबद्धता 100 प्रतिशत से बहुत कम रही है, और कुछ लोगों द्वारा रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाने का दबाव डाला। उन्होंने यूक्रेन युद्ध समाप्त होने तक चीन पर 50-100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का सुझाव दिया।

ट्रंप ने गठबंधन से सामूहिक रूप से कार्य करने का आग्रह किया और कहा कि नाटो सदस्य प्रतिबंधों पर सहमत होते ही वे "जाने" के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, "वैसे भी, जब

क्या रह होगा वक्फ संशोधन अधिनियम? सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनाएगा बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट सोमवार (15 सितंबर 2025) को वक्फ (संशोधन)

इस नए कानून को अंतरिम रूप से निलंबित किया जाए या नहीं।



अधिनियम 2025 पर अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाने जा रहा है। यह फैसला इस बात पर होगा कि क्या

गौरतलब है कि अदालत ने इस मामले में मई महीने में तीन दिन तक सुनवाई के बाद 22 मई को फैसला

सुरक्षित रख लिया था। कुल 21 याचिकाओं के जरिए इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

6 जून 2025 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण यूएमईईडी नामक डिजिटल पोर्टल पर छह महीने के भीतर कराने का आदेश दिया। इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इससे समुदाय पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा।

22 अगस्त को सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ताओं ने इस अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की, तो चीफ जस्टिस धुषण आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने साफ कहा कि चूंकि फैसला

पहले से सुरक्षित है, इसलिए अब अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता। याचिकाकर्ताओं के ने क्या दिए तर्क?

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में दलील दी कि 1954 से लेकर 2025 तक राज्य सरकारों और केंद्र का दायित्व था कि वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण और पहचान की जाए। लेकिन सरकार की इस असफलता का खामियाजा अब समुदाय को भुगतना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जिसमें अल्पसंख्यकों को अपनी संपत्तियों का प्रबंधन करने का अधिकार है। अन्य याचिकाकर्ताओं ने यह भी आपत्ति जताई कि नए कानून में वक्फ की स्थापना केवल ऐसे

'उत्कृष्ट अभिव्यक्ति का माध्यम हिन्दी'

चेतना है हिन्दी।

वर्तमान समय में अंग्रेजी ही आधुनिकता का आधार मानी जा रही है। भावी पीढ़ी की दृष्टि में हिन्दी का महत्व न्यून है। कितनी बड़ी विडम्बना है इस देश और समाज की कि हम अपने पूर्वजों की धरोहर जो हमें अनायास और सहजता से मिली है उसे ठुकरा रहे हैं और अंग्रेजों द्वारा परोसी गई भाषा को ग्रहण कर उसका उन्मयन कर रहे हैं। भाषा हमारी संस्कृति की अस्मिता और धरोहर है। यह केवल संवाद का माध्यम ही नहीं अपितु विचारों, भावनाओं एवं संवेदनाओं का उद्देश है। उन्नति के सोपान की ओर कदम बढ़ाते वक अंग्रेजी को भी सीखना चाहिए, परंतु हिन्दी के प्रति अपने प्रेम को भी जीवंत

अरशद वारसी और अक्षय कुमार ने दोस्तों में करवाई लड़ाई, नीलम ने उगला जहर?

(जीएनएस)।
'बिग बॉस 19' दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है। इसके हर एपिसोड में कुछ नया देखने को मिल रहा है, और प्रोमो वीडियो ने तो फैंस की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। हाल ही में, शो में 'जॉली एलएलबी 3' की टीम ने कोर्ट रूम ड्रामा पेश किया, जिसमें घर के सदस्यों को कठघरे में खड़ा किया गया।

कलर्स की तरफ से एक प्रोमो शेयर किया गया। जिसमें अरशद और अक्षय एक खेल खेलते हैं। तान्या मित्तल और कुनिका सदानंद कठघरे में थीं, जबकि नीलम गिरी उनके बीच खड़ी होकर सवालों के जवाब दे रही थीं। इस दौरान अक्षय कुमार ने नीलम से पूछा कि तान्या और कुनिका में से

टैरिफ उस पकड़ को तोड़ देंगे।"

अमेरिकी टैरिफ की धमकियों के बीच चीन ने रूस के साथ अपने ऊर्जा व्यापार का बचाव किया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने ब्लूमबर्ग न्यूज को एक ब्रीफिंग में कहा, "चीन के लिए दुनिया भर के सभी देशों, जिसमें रूस भी शामिल है, के साथ सामान्य आर्थिक, व्यापार और ऊर्जा सहयोग करना वैध और कानूनी है। हम अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार उचित ऊर्जा सुरक्षा उपाय अपनाना जारी रखेंगे।"

ट्रंप ने नाटो को चेतावनी दी कि उनके प्रस्तावों पर कार्रवाई करने में विफल रहने से अमेरिकी संसाधनों की बबादी होगी। उन्होंने कहा, "अगर नाटो ऐसा करता है, जैसा मैं कहता हूँ, तो युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा, और उन सभी जानें बच जाएंगी! यदि नहीं, तो आप मेरा समय, और संयुक्त राज्य अमेरिका का

समय, ऊर्जा और धन बर्बाद कर रहे हैं।"

एक दिन पहले, शुक्रवार को ब्रिटेन ने रूस से संबंधित प्रतिबंधों का एक नया पैकेज लॉन्च किया था, जिसमें रूसी तेल ले जाने वाले जहाजों, साथ ही रूसी हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और विस्फोटकों की आपूर्ति करने वाली कंपनियों और व्यक्तियों को लक्षित किया गया था।

यह आ'न तब आया है जब ट्रंप ने नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल के निरंतर आयात को लेकर भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था। उन्होंने रूसी कच्चे तेल खरीदने वाले देशों, जिसमें शीर्ष खरीदार चीन और भारत भी शामिल हैं, पर द्वितीयक प्रतिबंधों की धमकी भी दी है, यदि युद्ध समाप्त करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं होती है।

क्या रह होगा वक्फ संशोधन अधिनियम? सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनाएगा बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट सोमवार (15 सितंबर 2025) को वक्फ (संशोधन)

इस नए कानून को अंतरिम रूप से निलंबित किया जाए या नहीं।

अधिनियम 2025 पर अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाने जा रहा है। यह फैसला इस बात पर होगा कि क्या

गौरतलब है कि अदालत ने इस मामले में मई महीने में तीन दिन तक सुनवाई के बाद 22 मई को फैसला

सुरक्षित रख लिया था। कुल 21 याचिकाओं के जरिए इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

6 जून 2025 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण यूएमईईडी नामक डिजिटल पोर्टल पर छह महीने के भीतर कराने का आदेश दिया। इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इससे समुदाय पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा।

22 अगस्त को सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ताओं ने इस अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की, तो चीफ जस्टिस धुषण आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने साफ कहा कि चूंकि फैसला

पहले से सुरक्षित है, इसलिए अब अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता। याचिकाकर्ताओं के ने क्या दिए तर्क?

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में दलील दी कि 1954 से लेकर 2025 तक राज्य सरकारों और केंद्र का दायित्व था कि वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण और पहचान की जाए। लेकिन सरकार की इस असफलता का खामियाजा अब समुदाय को भुगतना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जिसमें अल्पसंख्यकों को अपनी संपत्तियों का प्रबंधन करने का अधिकार है। अन्य याचिकाकर्ताओं ने यह भी आपत्ति जताई कि नए कानून में वक्फ की स्थापना केवल ऐसे

अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा

था कि वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की परंपरा सौ साल से अधिक पुरानी है। 1923 के मुसलमान वक्फ अधिनियम से लेकर 1954 और उसके बाद के कानूनों तक, संपत्तियों की सूची और पंजीकरण को हमेशा महत्वपूर्ण माना गया है। सोमवार को आने वाला यह फैसला न केवल वक्फ अधिनियम 2025 के भविष्य का निर्धारण करेगा बल्कि देशभर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता के मुद्दे पर भी दूरगामी प्रभाव डालेगा।

रूप है। हिन्दी तो सर्वगुण सम्पन्न भाषा का दर्पण है। यह भाषा राष्ट्र के प्रति समर्पण है। एक स्वर और एक नाद से हम भारत वासियों को हिन्दी भाषा में अभिव्यक्ति को स्वीकारना चाहिए।

कथ्य के अनुरूप रचना संकलन को पहचान देती है हिन्दी।

पात्रो-चरित्रों के उद्घाटन का सजीव रूप है हिन्दी।

संवाद एवं प्रसंगानुकूल रोचकता की जनक है हिन्दी।

डॉ. रीना कहती, भाषा के सौन्दर्य की अनुपम छटा बिखेरती है हिन्दी।

डॉ. रीना रवि मालपानी (कवयित्री एवं लेखिका)

प्रेषक: डॉ. रीना रवि मालपानी

9039551172

कोर्ट रूम ड्रामा में अक्षय कुमार ने नीलम से यह भी पूछा कि क्या तान्या उन्हें पीठ में छुरा घोंप सकती हैं, जिस पर नीलम ने 'हां' में जवाब दिया।

इसके बाद, जब उनसे पूछा गया कि कौन अपनी बात से अक्सर पलट जाता है, तो नीलम गिरी ने कहा, "मुझे ऐसा लगता है ना सर कि मैंम को कई बार खुद भी याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या-क्या बोला है?" नीलम की बातें सुनकर अक्षय कुमार ने मजाकिया अंदाज में कहा कि ऐसा क्यों लग रहा है कि वह बच-बचाकर जवाब दे रही हैं। उन्होंने पूछा, "डर लगता है क्या आपको उनसे, सपने में आएंगी वो आपके, नागिन बनकर इस लेंगी।" रिपोर्टर्स की माने तो इस हफ्ते नतालिया घर से बेघर हो रही हैं।

कही यह बात

गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच हमेशा की तरह हाई-वोल्टेज होने वाला है। टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने भी खिलाड़ियों की तैयारी को लेकर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम का पूरा ध्यान केवल क्रिकेट पर है और खिलाड़ी मैदान में केवल जीत हासिल करने की सोच के साथ उतरेंगे।



बातचीत में कहा कि इंडिया एक जबर्दस्त टीम है और मुझे पूरा यकीन

है कि यह टूर्नामेंट भारत ही जीतेगा। इंडिया सबको मैदान से बाहर कर

देगा। टीम इंडिया ने अपने अभियान की शुरूआत शानदार अंदाज में की है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को केवल 9 विकेट से हराकर धमाकेदार जीत दर्ज की। भारत एशिया कप में खिताब का सबसे बड़ा दावेदार है।

कप में खिताब का सबसे बड़ा दावेदार है।

अपर महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे द्वारा साबरमती स्टेशन एवं इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपो साबरमती का निरीक्षण



पश्चिम रेलवे के अपर महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार ने 13 सितम्बर 2025 को अहमदाबाद मंडल के साबरमती रेलवे स्टेशन तथा इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपो (कउऊ) साबरमती का व्यापक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान श्री प्रदीप कुमार ने साबरमती स्टेशन पर पुनर्विकास कार्यों के तहत

नवनिर्मित यात्री सुविधाओं जैसे कि कोनकोर्स हॉल, वेटिंग एरिया, टिकट बुकिंग विंडो, यात्रियों के लिए अलग-अलग एंट्री और एग्जिट पथ, लिफ्ट तथा स्टेशन पर उपलब्ध अन्य सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने सभी प्लेटफार्मों पर जाकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा

निर्माणार्थीन फुट ओवर ब्रिज, एस्केलेटर्स, कवर शेड आदि विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

इस अवसर पर उप मुख्य परियोजना प्रबंधक (अहमदाबाद) श्री अनंत कुमार ने साबरमती स्टेशन पर जारी पुनर्विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी अपर महाप्रबंधक

अहमदाबाद-बरौनी एक्सप्रेस का सहरसा तक विस्तार

रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन संख्या 19483/19484 अहमदाबाद-बरौनी एक्सप्रेस को सहरसा तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है: ट्रेन संख्या 19483 अहमदाबाद-

सहरसा एक्सप्रेस अहमदाबाद से निर्धारित समय 00.35 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 22.55 बजे सहरसा पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 19484 सहरसा-अहमदाबाद एक्सप्रेस 14 सितंबर 2025 से सहरसा से 16.40 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे

दिन 11.55 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। बरौनी से सहरसा के बीच यह ट्रेन बेगूसराय, खगड़िया, मानसी और सिमरी बख्तियारपुर स्टेशनों पर रुकेगी।

अहमदाबाद से बरौनी के बीच इस ट्रेन के आगमन/प्रस्थान समय में कोई

बदलाव नहीं किया गया है।

ट्रेनों के उहराव और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

11 साल के लिव इन रिलेशन का ऐसा खौफनाक अंत

हत्या की वजह जानकर चौंक जाएंगे

उत्तराखंड के हरिद्वार में एक व्यक्ति ने अपने लिव-इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या कर दी। बाद में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों 11 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। दोनों की आठ साल की एक बेटी भी है। हत्या की वजह सोशल मीडिया में सक्रियता और महिला का किसी ओर से संपर्क होने का शक बताया जा रहा है।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला हरिद्वार रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के भभूतावाला बाग का है। जहां जिला अस्पताल के ड्राइवर ने अपनी लिव-इन पार्टनर की लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी।



आरोपी ने हत्या के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया।

आरोपी युवक मुकेश पुजारी पिछले करीब 11 साल से शिवलोक कॉलोनी में रहने वाली पिंग्की के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था। जो कि ब्यूटी पार्लर भी चलाती थी।

दोनों की आठ साल की एक बेटी भी है। मुकेश की पहली शादी भी हो चुकी है और उसकी पहली पत्नी से दो जवान बेटे हैं, जो अलग रहते हैं।

महिला 11 साल पहले मुकेश के लिए अपने दो बच्चे और पति को छोड़कर आई थी। जिसके बाद से

दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थीं। मुकेश ने अपनी लिव इन पार्टनर के लिए पास में ब्यूटी पार्लर भी खुलवाकर दिया। 11 साल तक सबकुछ सही चल रहा था,लेकिन अब पिंग्की की सोशल मीडिया पर सक्रियता और रील बनाना मुकेश को पसंद नहीं थी।

शक और विवाद की वजह से दोनों के बीच मममुटाव शुरू हुआ जिसका खौफनाक अंत हो गया। बताया जा रहा है कि घटना वाली रात करीब एक बजे मुकेश ने पिंग्की को फोन कर बाहर बुलाया। दोनों के बीच कहासुनी हुई और बात बढ़ने लगी। बाद में मुकेश ने अपनी पार्टनर की बेरहमी से हत्या कर दी। बाद में मुकेश ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया।

'अपने बायोडाटा में ये लिखिए', विश्वविद्यालय कुलपति के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीमकोर्ट का आया अहम फैसला

(जीएनएस)। पश्चिम बंगाल एनयूजेएस विश्वविद्यालय के कुलपति निर्मल कांति चक्रवर्ती के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि, न्यायालय ये फैसला चुनाते हुए बड़ा आदेश भी दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि कुलपति के रिज्यूम में ये केस और आरोप लिखा जाए। इसका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

पीड़िता ने 26 दिसंबर 2023 को औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी, जबकि यौन उत्पीड़न अप्रैल 2019 में हुआ था। स्थानीय शिकायत समिति (एलसीसी) ने शिकायत को समय-बाधित मानते हुए खारिज कर दिया था, क्योंकि शिकायतकर्ता ने तीन महीने की निर्धारित सीमा और छह महीने की विस्तारित सीमा दोनों का उल्लंघन किया था।

पीड़िता के अनुसार, कुलपति चक्रवर्ती ने जुलाई 2019 में विश्वविद्यालय में कार्यभार संभाला। दो महीने बाद, 8 सितंबर को, उन्होंने पीड़िता को अपने कार्यालय में बुलाया और डिनर के लिए अनुरोध किया। उन्होंने महिला के हाथ को छुआ,



जिससे वह असहज महसूस कर रही थी। इसके बाद महिला चुपचाप वहां से चली गई।

अक्टूबर 2019 में, कुलपति ने उसे दोबारा अपने कार्यालय में बुलाया

और डिनर के प्रस्ताव के बारे में पूछा। पीड़िता ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और कहा कि वह केवल पेशेवर संबंध बनाए रखना चाहती है। इसके बाद, कुलपति ने कथित तौर पर यौन संबंध बनाने की मांग की और उसे धमकी दी।

अक्टूबर 2019 में, पीड़िता की पीड़िता ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और कहा कि वह केवल पेशेवर संबंध बनाए रखना चाहती है। इसके बाद, कुलपति ने कथित तौर पर यौन संबंध बनाने की मांग की और उसे धमकी दी।

कहा, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद, उसे करियर बर्बाद करने की धमकी दी गई।

29 अगस्त 2023 को, सेंटर ऑफ फाइनेंशियल, रेगुलेटरी एंड गवर्नंस स्टडीज (CFRGS) से महिला को निदेशक पद से हटा दिया गया। उसी समय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और नेशनल फाउंडेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नंस (NFCG) से प्राप्त अनुदान के दुरुपयोग के मामले में पीड़िता के खिलाफ जांच शुरू की गई। कार्यकारी परिषद ने एनयूजेएस को 1 लाख रुपये तुरंत वापस करने का आदेश दिया। पीड़िता ने ई-मेल के माध्यम से कार्यकारी परिषद और कुलपति से उत्पीड़न और बदले की शिकायत की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निदेशक पद से हटाना यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह एनएफसीजी की स्वतंत्र रिपोर्ट पर आधारित था। इस कार्रवाई को पिछली कथित घटनाओं से जोड़ा नहीं जाएगा।

पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के पीछे क्या है मजबूरी? पूर्व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का आया बड़ा बयान

(जीएनएस)। एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर सियासत गरमा गई है। विपक्षी पार्टियां जहां इस मैच के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों पर 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाने के बाद कई पूर्व क्रिकेटर्स और प्रशंसकों ने इस मैच के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। सोशल ममीडिया पर भी इस पर

तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने इसकी वजह बताई है। पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के पीछे व या है मजबूरी? अनुराग ठाकुर ने बताया कि एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC)

बावजूद आखिर ये मैच भारत के लिए खेलना व या जरूरी है? पूर्व खेल मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने इसकी वजह बताई है। पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के पीछे व या है मजबूरी? अनुराग ठाकुर ने बताया कि एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC)

द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में ऐसे मुकाबलों से बचा नहीं जा सकता। यदि कोई देश ऐसे टूर्नामेंट में खेलने से मना करता है, तो उसे प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ सकता है या उसे अंक गंवाने पड़ सकते हैं। अगर भारत नहीं खेलता पाक के साथ मैच तो क्या होगा? अनुराग ठाकुर ने न्यूज एजेंसी अटक द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में बताया, "जब एसीसी या आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं, तो देशों के लिए खेलना अनिवार्य हो जाता है।

एमाजान इंजीनियर ने किया फिलिस्तीन का समर्थन, कंपनी का एक्शन बना ग्लोबल चर्चा का मुद्दा

(जीएनएस)। ई-कॉमर्स कंपनी Amazon»»f ने फिलिस्तीनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर अहमद शाहरूर को सस्पेंड कर दिया है। इसकी वजह उनके द्वारा इजराइली सरकार और Amazon के बीच हुए समझौते Project Nimbus का विरोध बताया जा रहा है।

शाहरूर का कहना है कि यह प्रोजेक्ट इजराइल को एआई और डेटा सेंटर जैसी सुविधाएं देता है, जिससे फिलिस्तीनियों पर निगरानी और दमन आसान हो जाता है। वहीं, Amazon ने आरोप लगाया कि शाहरूर ने कंपनी की नीतियों का उल्लंघन किया है। यह मामला न सिर्फ टेक कंपनियों की नीतियों बल्कि फिलिस्तीनी कर्मचारियों की आवाज दबाए जाने पर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है।

क्यों किया गया अहमद शाहरूर को सस्पेंड?

अहमद शाहरूर पिछले तीन सालों से Amazon की Whole Foods डिवीजन में सिएटल ऑफिस से काम कर रहे थे। उन्होंने Slack चैनलों और एक ओपन लेटर के जरिए Project Nimbus

का विरोध किया था। शाहरूर का आरोप है कि यह प्रोजेक्ट इजराइल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर जैसी

सरकार को उन्नत तकनीकी सेवाएं देना है। लेकिन मानवाधिकार संगठनों और कर्मचारियों का मानना है कि इस प्रोजेक्ट से फिलिस्तीनियों के खिलाफ



आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराता है, जिसका इस्तेमाल फिलिस्तीनी लोगों पर नियंत्रण और निगरानी के लिए किया जा सकता है। विरोध के तुरंत बाद Amazon ने उन्हें नोटिस भेजा और सस्पेंड कर दिया।

प्रोजेक्ट निम्बस और विवाद Project Nimbus 2021 में Google और Amazon की साझेदारी में शुरू हुआ था। इसका मकसद इजराइली

सैन्य और निगरानी गतिविधियों को और बढ़ावा मिलेगा। अहमद शाहरूर और अन्य कर्मचारियों का कहना है कि इस तरह की डील टेक कंपनियों की नैतिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़ा करती है।

फिलिस्तीनी कर्मचारियों की मुश्किलें शाहरूर ने कहा कि Amazon लगातार फिलिस्तीनियों की आवाज

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 की शुरूआत, जानिए कहां और कैसे करें आवेदन, क्या हैं पात्रता

(जीएनएस)। शहर में सपनों का घर तलाश रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। देहरादून नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत आवास निर्माण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के तहत 2.75 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

इसमें किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन ने दलाली से बचने की अपील की है। आवासविहीन शहरी आबादी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण योजना चलाई जा रही है। जिसके लिए नगर निगम ने आवेदन आमंत्रित किए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 की शुरूआत सितंबर 2024 में की गई थी और यह अगले पांच वर्षों के लिए यह योजना प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों

में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न और मध्यम आय वर्ग के

है। इस योजना के अंतर्गत विधवा, एकल महिला, दिव्यांगजन, वरिष्ठ



परिवारों को आवास निर्माण या खरीद में केंद्रीय सहायता प्रदान करना है।

योजना के तहत 2.25 लाख की सहायता केंद्र सरकार और 50 हजार रुपये राज्य सरकार की ओर से लाभार्थियों को दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत खाली भूखंड पर मकान बनाने वाले या कच्चे मकानों में रह रहे परिवारों को प्राथमिकता दी जाती

नागरिक, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक और सफाई कर्मियों जैसे वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है।

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है योजना पारदर्शी और लाभार्थी केन्द्रित है।

योजना में वही परिवार पात्र होंगे जिनमें पति-पत्नी और अविवाहित

सीएम मोहन यादव के हॉट एयर बैलून में लगी आग? इस पूरी घटना पर कलेक्टर ने बता दी पूरी सच्चाई

(जीएनएस)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार सुबह गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट में एक बड़े हादसे से बच गए। जानकारी के अनुसार, वे हॉट एयर बैलून की सवारी करने पहुंचे थे। तेज हवा और अचानक लगी आग ने हालात तनावपूर्ण बना दिए।

गनीमत रही कि सुरक्षा गार्ड और स्टाफ ने तत्काल स्थिति को काबू में कर लिया और किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई। मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं।

सीएम मोहन यादव हिंगलाज रिसॉर्ट में रात बिताने के बाद सुबह हॉट एयर बैलून की सवारी करने पहुंचे। उस समय हवा की रफ्तार लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसकी वजह से बैलून उड़ान नहीं भर सका। इसी दौरान बैलून के निचले हिस्से में अचानक आग लग गई। मौके पर मौजूद स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत आग बुझाई और ट्रॉली को संभाला, जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद थे। एमपी के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक की खबरें भ्रामक। हॉट एयर

बैलून में आग जलने को बताया सुरक्षा में चूक। मंदसौर कलेक्टर ने किया

मुख्यमंत्री ने बोटिंग और बाइक बोट का भी आनंद लिया



इंकार।

सुरक्षा कर्मियों की तत्परता से टला बड़ा हादसा

आग लगने के बाद स्थिति थोड़ी गंभीर हो गई थी, लेकिन स्टाफ की त्वरित कार्रवाई से सीएम समेत अन्य जनप्रतिनिधियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहत की बात यह रही कि बैलून उड़ान भरने से पहले ही आग लगी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने चंबल नदी की सैर की और बोटिंग का आनंद लिया। उनके साथ सांसद सुधीर गुप्ता, गरोट विधायक चंद्र सिसोदिया, कमिश्नर आशीष सिंह, आईजी उमेश जोगा, कलेक्टर अदिति गर्ग, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने बाइक बोट की सवारी भी की और पानी की

दबाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी कर्मचारियों को स्वतंत्र रूप से राय रखने से रोक रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया कि फ्रांस में भी एक कर्मचारी को सोशल मीडिया पर इजराइल की आलोचना करने के चलते नौकरी से निकाला गया। शाहरूर के अनुसार यह सिर्फ उनकी नौकरी नहीं बल्कि फिलिस्तीनी पहचान और अधिकारों को दबाने की कोशिश है।

टेक कंपनियों में बढ़ते विरोध की लहर

Amazon ही नहीं, Microsoft में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। कुछ समय पहले कंपनी ने चार कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया था क्योंकि उन्होंने इजराइल को दी जा रही तकनीकी मदद का विरोध किया था। यह घटनाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि बड़ी टेक कंपनियों में इजराइल से जुड़ी डीलस के खिलाफ कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ रही है।

बेटे-बेटियां शामिल हैं और जिनके पास किसी भी राज्य या शहर में पक्का आवास नहीं है। जिन्होंने पिछले 20 वर्षों में किसी अन्य आवासीय योजना का लाभ नहीं लिया हो, इसके अलावा, लाभार्थी को 01 सितंबर 2024 से पहले नगर निगम क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है।

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत बने मकान महिला मुखिया के नाम या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर होंगे। आवश्यक दस्तावेज

आवेदक और परिवार के सभी सदस्यों का आधार विवरण आवेदक का बैंक खाता विवरण (जो आधार से जुड़ा हो) तीन लाख रुपये से कम आय का प्रमाण पत्र या स्व-घोषणा भूमि संबंधी दस्तावेज (लाभार्थी आधारित निर्माण घटक के अंतर्गत)

स्व-घोषित शपथ पत्र आवेदक का बैंक खाता विवरण (जो आधार से जुड़ा हो) तीन लाख रुपये से कम आय का प्रमाण पत्र या स्व-घोषणा भूमि संबंधी दस्तावेज (लाभार्थी आधारित निर्माण घटक के अंतर्गत)

स्व-घोषित शपथ पत्र आवेदक का बैंक खाता विवरण (जो आधार से जुड़ा हो) तीन लाख रुपये से कम आय का प्रमाण पत्र या स्व-घोषणा भूमि संबंधी दस्तावेज (लाभार्थी आधारित निर्माण घटक के अंतर्गत)

अब इस पूरी घटना के बाद कलेक्टर अदिति गर्ग ने कहा कि एयर बैलून की पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा के सभी मानकों का पालन किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री केवल एयर बैलून देखने पहुंचे थे और किसी प्रकार की सुरक्षा में चूक नहीं हुई।

यह पूरा घटनाक्रम उस समय हुआ जब मुख्यमंत्री प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट पहुंचे थे। तेज हवा और अचानक आग ने एक पल के लिए अफरा-तफरी मचा दी, लेकिन सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से स्थिति संभाल ली गई।

पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले गंभीर का सख्त मैसेज, कोच ने बताई टीम मीटिंग के अंदर की बात

(जीएनएस)। एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला 14 सितंबर यानी रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच हर बार की तरह सिर्फ क्रिकेट का मुकाबला नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। इस बार यह भिड़ंत और भी संवेदनशील हो गई है क्योंकि

अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। उसी घटना के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान किसी

मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग मैच के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह और केदार जाधव ने भी साफ शब्दों में कहा



है कि इस हालात में पाकिस्तान के खिलाफ खेलना सही नहीं है। हालांकि बीसीसीआई ने सरकार के निर्देश पर

फैसला लिया कि द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगी, लेकिन बहु-देशीय टूर्नामेंटों में भारत को खेलना ही पड़ेगा। भारत के अफिरस्टेट कोच रयान टेन डोशाटे ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खिलाड़ी हालात को समझते हैं और वे मैदान पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे। उन्होंने कहा कि यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है।

लखनऊ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ऐलान, नई हिंदी फिल्म शुभ संगम की घोषणा

फिल्म एक्टर राकेश बेदी ने कहा – फिल्मों को प्रोत्साहित कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार

लखनऊ 13 सितम्बर। नवाबों का शहर लखनऊ अब सिनेमा के रंग में रंगने जा रहा है। यहां आयूब खान द्वारा शुरू और आयोजित लखनऊ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ऐलान किया गया है। यह तीन दिन का फिल्म महोत्सव 2 से 4 दिसम्बर 2025 तक चलेगा, जिसमें फिल्मकारों, कलाकारों और दर्शकों को एक साथ लाकर कहानियों का जश्न मनाया जाएगा। इधर मशहूर फिल्म एक्टर राकेश बेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार फिल्मों को जिस तरह से प्रोत्साहित कर रही है, उसके लिए वह बधाई के पात्र है। उन्होंने लखनऊ की हरियाली के साथ साथ खानपान और तहजीब की भी तारीफ की।

फेस्टिवल के फाउंडर, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर व डिस्ट्रीब्यूटर आयूब खान ने लखनऊ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में कहा हलहलखनऊ एक शानदार शहर है

होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया ने सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया

सड़क सुरक्षा के प्रति सोच बदलने के लिए 2400 से अधिक स्कूल के छात्रों और स्टाफ मेंबर्स को जोड़ा गया

आगरा : होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया ने अपनी सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान को आगरा में आयोजित किया, जिसमें राजा बलवंत सिंह मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस, पुष्पांजलि कॉलेज ऑफ नर्सिंग और अग्रवान हेरिटेज यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भाग लिया। 2400 से अधिक छात्रों की भागीदारी के साथ, इस पहल का उद्देश्य संरचित प्रशिक्षण और इंटरैक्टिव लर्निंग के माध्यम से जिम्मेदार सड़क उपयोग की संस्कृति को मजबूत करना था।

कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया गया कि शुरूआती शिक्षा भविष्य के सवारों और नागरिकों को गढ़ने में अहम भूमिका निभाती है। छात्रों को सड़क सुरक्षा के व्यावहारिक पहलुओं

शानो ओ शौकत से शुरू होगा दादा मियां का 118 वां उर्स मुबारक



15 से 19 सितम्बर तक चलेगा उर्स उर्स में हिन्दुस्तान के कई हिस्सों से आयेगे अकीदतमंद दादा मियां की दरगाह भाई चारगी और अमन ओ शान्ति का मरकज: सबाहत हसन शाह लखनऊहजरत ख्वाजा मोहम्मद नबी रजा शाह अलमारूफ दादा मियाँ २० अ० के 118वें सालाना उर्स का आगाज निहायत ही शानो ओ शौकत के साथ आज से आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। इस दरगाह की सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ दुनिया भर से हर मजहब और हर कौम के लोग बेशुमार तादात में अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए इकटठा होते हैं और दादा मियाँ के फैजान और कमालात से मालामाल होते हैं।सज्जादा नशीन व मुतावल्ली हजरत

धातानगर पंचायत क्षेत्र में सफाईकर्मियों के साथ मारपीट का मामला

धातानगर पंचायत क्षेत्र में सफाईकर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। 12 सितंबर की शाम को नगर पंचायत की अटेलवा स्थित जमीन पर यह घटना हुई।

कूड़ा गाड़ी का चालक कुमार पासवान जब यूपी 71 सिटी 1911 नंबर की गाड़ी से कूड़ा फेंकने पहुंचे, तब कृपा शंकर शुक्ला और राहुल शुक्ला ने उन्हें रोक दिया। दोनों ने दावा किया कि यह उनकी निजी जमीन है। इसके बाद उन्होंने चालक से

और यहां सिनेमा को बेहद प्यार मिलता है। दिसम्बर के पहले हफ्ते में हम तीन दिन का यह फिल्म महोत्सव



आयोजित कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि राखेश बेदी, सोहम पी. शाह और फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बी.एन. तिवारी जैसे बड़े नाम इस खास मौके पर हमारे साथ हैं।' इसी मौके पर आयूब खान ने अपनी आने वाली हिंदी फीचर फिल्म शुभ संगम की भी घोषणा की।

फिल्म निर्देशक और जूरी सदस्य सोहम पी. शाह ने कहा हलहामाननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश राज्य में, हम यह प्रतिष्ठित फेस्टिवल लखनऊ के सहारागंज

स्थित पीवीआर सिनेमा में शुरू कर रहे हैं। इस फेस्टिवल का मकसद यहां के प्रतिभाशाली लेखक, निर्देशक और



कलाकारों को प्रोत्साहित करना है। यह महोत्सव 2 से 4 दिसम्बर 2025 तक पीवीआर सिनेमा, सहारागंज, लखनऊ में होगा। और खास बात यह है कि आयूब खान जी की नई हिंदी फीचर फिल्म शुभ संगम की शूटिंग भी नवंबर 2025 से उत्तर प्रदेश में ही शुरू होगी।'

ख्यातिप्राप्त वरिष्ठ फिल्म अभिनेता राखेश बेदी, जो फेस्टिवल में जूरी सदस्य भी होंगे और फिल्म शुभ संगम में भी अभिनय करेंगे, ने कहा हलहलखनऊ इंटरनेशनल फिल्म

फेस्टिवल के लॉन्च और फिल्म शुभ संगम की घोषणा पर मैं आयूब खान और लखनऊ की जनता को बधाई देता हूं। मुझे खुशी है कि मैं इस फेस्टिवल में जूरी सदस्य होने के साथ-साथ फिल्म शुभ संगम में भी एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा हूं।' उन्होंने आयूब खान से अपने लंबे जुड़ाव को भी साझा किया। कह कि हलहआयूब खान साहब से मेरा रिश्ता कई साल पुराना है। मुंबई में भी मैं उनके द्वारा आयोजित सिनीड्रीम्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का दो साल से जूरी सदस्य रहा हूं। उनकी फिल्म बे-लगाम में भी मैंने अहम किरदार निभाया था। वे न सिर्फ एक प्रतिभाशाली लेखक और निर्देशक हैं बल्कि एक ईमानदार और अच्छे इंसान हैं। हमारे बीच की दोस्ती और रचनात्मक सफर मेरे लिए बहुत मायने रखता है।'

लखनऊ में लखनऊ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और शुभ संगम दोनों की घोषणा के साथ ही शहर एक बड़े सांस्कृतिक उत्सव के लिए तैयार है, जहां सिनेमा, कला और रचनात्मकता का जश्न मनाया जाएगा।

स्कूलों और कॉलेजों को शामिल करके एचएमएसआईयह सुनिश्चित करता है कि युवा अपनी आवाज के जरिए यह संदेश घरों समुदायों तक पहुंचाएँ, जिससे इसका असर सीधे प्रतिभागियों से कहीं आगे तक फैल सके।

आगरा में यह पहल एचएमएसआईके व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा शिक्षा को समाज के विभिन्न स्तरों पर एकीकृत करना है। हर गतिविधि एचएमएसआईके लगातार चल रहे प्रयासों को मजबूत बनाती है, ताकि सुरक्षा शिक्षा सुलभ, सहज और प्रभावशाली बन सके और ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो गतिशीलता में जिम्मेदारी को सबसे पहले रखे। ऐसी निरंतर पहलों से याद दिलाया जाता है कि सड़क पर सोच-समझकर किए गए कार्य सिर्फ स्वयं की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहते, बल्कि आसपास सभी की सुरक्षा में योगदान करते हैं।

ऐसे अभियानों के माध्यम से एचएमएसआईआने-जाने की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का समाधान कर रहा है युवाओं में सड़क पर जिम्मेदारी की सोच विकसित करना। इसका मकसद केवल जागरूकता फैलाना नहीं है, बल्कि लंबे समय तक व्यवहार में बदलाव लाना है, ताकि सही और समझदारी से लिए गए फैसले रोजमरां की आदत बन जाएँ।

सेवा पखवाड़ा की तैयारी को लेकर भाजयुमो की बैठक संपन्न

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर आयोजन में जुटा युवा मोर्चा (जीएनएस)।

सीतापुर। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस (17 सितम्बर) से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस (2 अक्टूबर) तक ह्रसेवा पखवाड़ाह का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आज भाजपा कार्यालय, सीतापुर में बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक की अध्यक्षता भाजयुमो जिलाध्यक्ष सचिन मिश्रा ने की। इस अवसर पर प्रवासी के रूप में क्षेत्रीय

(जीएनएस)। सीतापुर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में गोवंश की निर्मम हत्या का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सिधौली कोतवाली क्षेत्र के अटरिया थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे झाड़ियों से गोवंश का कटा हुआ सिर, खाल और अन्य अवशेष बरामद हुए हैं, जबकि उसका मांस गायब है। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश है।

जानकारी के मुताबिक, यह घटना अटरिया थाना क्षेत्र के हल्का नंबर 1 में कांवण गांव के सामने, नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक के बीच की झाड़ियों में हुई। माना जा रहा है कि अज्ञात गोतस्करों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर इस घटना को अंजाम दिया। ये गोवंश का गला काटकर उसका सिर और खाल वहीं छोड़कर मांस लेकर फरार हो गए। पुलिस और प्रशासन का त्वरित एक्शन

सुबह जैसे ही इस निर्मम घटना की जानकारी मिली, पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही हल्का इंचार्ज विशंभर दयाल तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने तत्काल अपने वरिष्ठ

पुलिस और प्रशासन का त्वरित एक्शन

सुबह जैसे ही इस निर्मम घटना की जानकारी मिली, पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही हल्का इंचार्ज विशंभर दयाल तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने तत्काल अपने वरिष्ठ

विधायक अनिल कुमार वर्मा ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा

(जीएनएस)।

सीतापुर। विकास खण्ड बेहटा क्षेत्र में शारदा नदी के कटान से प्रभावित लखनीपुर गांव में शनिवार को क्षेत्रीय विधायक अनिल वर्मा ने दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की चिंताओं को समझा। विधायक ने मौके पर मौजूद सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कटान रोकने के लिए किए जा रहे बचाव कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और गांव को कटान से सुरक्षित करने के लिए स्थाई समाधान लागू करने के निर्देश दिए। गांव की महिलाओं ने विधायक अनिल वर्मा के सामने अपनी परेशानियां रखीं, जिसमें नदी के कटान से घरों और

बच्चों में रीढ़ की हड्डी की समस्या से बचाव के लिए समय पर पहचान जरूरी

जटिल सर्जरी से तीन विभिन्न मरीजों में जागी नई उम्मीद एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, खान पान का ध्यान रखकर स्पाइन को रखें स्वस्थ

लखनऊ, 13 सितम्बर, 2025: गोरखपुर निवासी 12 वर्षीय मोहिनी जन्म से ही दूसरे बच्चों से अलग थीं। उनसे शरीर का ऊपरी हिस्सा आगे की ओर झुका हुआ था और पीठ की ओर एक बड़ा उभार (कूबड़) था जो कपड़े पहनने के बाद भी छिपाया नहीं जा सकता था। इससे न सिर्फ उन्हें चलने फिरने में परेशानी होती थी बल्कि अपनी उम्र में बच्चों में चर्चा का विषय थीं। इस शारीरिक और मानसिक पीड़ा को उन्होंने लंबे समय तक झेला। सिर्फ मोहिनी ही नहीं बल्कि उनके जैसे कई बच्चे और बड़े रीढ़ में झुकाव की समस्या से जूझ रहे हैं। इस तरह की परेशानी से जूझने वाले मरीजों के लिए मेदांता लखनऊ में उम्मीद की नई किरण जग रही है, जहां इस जटिल सर्जरी का सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।

मंत्री शिवंजलि पाण्डेय तथा क्षेत्रीय कार्यसमिति सदस्य सोमी शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहीं। बैठक में भाजपा सीतापुर के महामंत्री विश्राम सागर राठौर भी मौजूद रहे।



जिला पदाधिकारी प्रतीक पाण्डेय ने बताया बैठक का मुख्य उद्देश्य

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस 17 सितम्बर को आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर की तैयारी करना रहा। इसमें शिविर को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की

जिम्मेदारियों का निर्धारण किया गया तथा अधिक से अधिक युवाओं को

गोवंश हत्या का सनसनीखेज मामला,मौके पर पहुंची विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल पुलिस प्रशासन अलर्ट, दोषियों की तलाश जारी

अधिकारियों को इसकी सूचना दी। अटरिया थाना प्रभारी उमाकांत शुक्ला भी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सिधौली क्षेत्र अधिकारी



कपूर कुमार को घटना से अवगत कराया।

क्षेत्राधिकारी कपूर कुमार ने मामले की गंभीरता को समझते हुए गहनता से जांच के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस टीम को जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

एडिशनल एसपी ने दिए सख्त निर्देश

इसी दौरान, थाना समाधान दिवस के लिए जा रहे सीतापुर के एडिशनल

एसपी दुर्गेश कुमार सिंह ने मौके पर रुककर घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने इस घटना पर कड़ा रुख अपनते हुए अटरिया एसओ को

कई सख्त निर्देश दिए। एडिशनल एसपी ने एसओ को पिछले पाँच वर्षों में गोवंश से संबंधित मामलों के संदिग्धों की एक सूची तैयार करने और वर्तमान मामले की गहनता से जांच करने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना से जुड़े सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए।

फोरेंसिक टीम और बजरंग दल की भूमिका

कई सख्त निर्देश दिए। एडिशनल एसपी ने एसओ को पिछले पाँच वर्षों में गोवंश से संबंधित मामलों के संदिग्धों की एक सूची तैयार करने और वर्तमान मामले की गहनता से जांच करने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना से जुड़े सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। फोरेंसिक टीम और बजरंग दल की भूमिका

खेतों को होने वाला नुकसान प्रमुख के लिए मजबूत उपायों की मांग की।



था। ग्रामीणों ने नदी के किनारे सुरक्षा

विधायक अनिल वर्मा ने ग्रामीणों

रक्तदान के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया गया।

बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत होने वाले सभी कार्यक्रमों को जनभागीदारी से सफल बनाया जाएगा और समाज सेवा के कार्यों को गाँव-गाँव तक पहुँचाया जाएगा।

बैठक में भाजयुमो जिला महामंत्री तरुण शुक्ला, अनूप विश्वकर्मा जिला उपाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, नमन वर्मा, जिला मंत्री वैभव सिंह व अन्य पदाधिकारियों में अंकुल तिवारी, अखिलेश शर्मा, राजा शुक्ला, वासुदेव पाण्डेय, ऋषभ पाण्डेय, आशु सिंह, कमलेन्द्र मिश्रा, सूर्य प्रताप सिंह, धर्मेन्द्र यादव, मृत्युंजय, कन्हैया आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, मौके पर फोरेंसिक टीम भी बुलाई गई। टीम ने घटनास्थल से नमूने (साक्ष्य) एकत्रित किए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। इससे पुलिस को दोषियों तक पहुंचने में मदद मिलने की उम्मीद है।

सूचना पर पहुंचे बजरंग दल के पदाधिकारी इस बीच, बजरंग दल के जिला सहसंयोजक अजय दीक्षित ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए अटरिया थाना प्रभारी को लिखित शिकायत (तहरीर) दी है। उन्होंने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बजरंग दल के जिला मंत्री शिवम, प्रांत के अधिकारी बच्चै प्रसाद वाजपेयी और उपाध्यक्ष राम मोहन जन्मेजय ने भी इस घटना को हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला बताते हुए अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है।

इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और अपराधियों की तलाश में जुट गया है। स्थानीय लोग भी पुलिस से जल्द से जल्द कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और अपराधियों की तलाश में जुट गया है। स्थानीय लोग भी पुलिस से जल्द से जल्द कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कटान रोकने के कार्यों को तेज करने और गांव की निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्थाई समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में कटान की समस्या से ग्रामीणों को निजात मिल सके। इस अवसर पर अतुल वर्मा, पईद्रपाल चौधरी सदस्य जिला पंचायत, प्रहलाद कन्नौजिया प्रतिनिधि सदस्य जिला पंचायत, उरूज अहमद,श्रेष्ठ रिजवान अतीक, जावेद खान, जावेद नसीर, मो. आलम, ग्राम प्रधान नबी अहमद सहित कई अन्य ग्रामीण और स्थानीय नेता मौजूद रहे।

समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कटान रोकने के कार्यों को तेज करने और गांव की निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्थाई समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में कटान की समस्या से ग्रामीणों को निजात मिल सके। इस अवसर पर अतुल वर्मा, पईद्रपाल चौधरी सदस्य जिला पंचायत, प्रहलाद कन्नौजिया प्रतिनिधि सदस्य जिला पंचायत, उरूज अहमद,श्रेष्ठ रिजवान अतीक, जावेद खान, जावेद नसीर, मो. आलम, ग्राम प्रधान नबी अहमद सहित कई अन्य ग्रामीण और स्थानीय नेता मौजूद रहे।

बाद उनका कूबड़ काफी हद तक कम हो गया है। पहले जहां 90 डिग्री का कर्व था, अब वह 40 डिग्री से भी कम रह गया है। अब वह सामान्य जीवन जी पा रही हैं। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारियां सिर्फ वयस्कों तक सीमित नहीं हैं, बच्चों और किशोरों में भी ये समस्याएं तेजी से सामने आ रही हैं। समय पर पहचान और सही इलाज न मिलने पर ये दिक्कतें न सिर्फ बच्चों के आत्मविश्वास को प्रभावित करती हैं बल्कि उनकी चलने-फिरने की क्षमता और जीवन की गुणवत्ता पर भी स्थायी असर डाल सकती हैं। इसलिए अभिभावकों को सावधान